(ख) दालों का आयात मुक्त रूप से अनुमत है । पिछले तीन वर्षो के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा और कीमत नीचे दी गई है:–

वर्ष	मात्रा(लाख टन में)	मुल्य (करोड़ रूपए में)
1995-96	4.91	685.57
1996-97	6.55	890.34
1997-98	6.59	833.64

पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकारी खाते पर दालों का कोई आयात नहीं किया गया ।

(ग) दालों के आयात में कमी लाने के प्रयोजन से दालों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 26 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम नामतः राष्ट्रीय दाल विकस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ।1

Oil imports affecting domestic solvent extraction plants

1854. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether excessive oil imports flooding the market have resulted in domestic solvent extraction plants plagued by excess idle capacity; and

(b) if so, the steps proposed to protect such domestic processors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) Domestic solvent extraction plants are working to well below their installed capacity due to shortage or oil bearing material and not due to excessive oil imports. The Short-fall between demand and supply is currently estimated at between 14-15 lakh MTs. Against this, the import of 11.3 lakh MTs of edible oils in the financial year 1997-98 cannot be considered as excessive.

भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली राज-सहायता

1855. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि राज-सहायत के रूप में प्रदान की गई;

(ख) यह सहायता किस प्रयोजनार्थ प्रदान कि गई और तत्संबंधी राशि कितनी थी;

(ग) निगम द्वारा उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः कितनी धनराशि की मांग़ की गई थी; और

(घ) निगम को उक्त अवधि में वास्तव में कितना नुकसान हुआ था और हर्जाने के रूप में निगम को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों (गेंहूं और चावल) की इकनामिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं आदि के अधीन वितरण से उनकी बिक्री प्राप्ति के बीच के अन्तर के भुगतान उपभोक्ता सब्सिडि के रूप में करती है । बफर स्टाक रखने की लागत प्रतिsपूर्ति भी निगम को खाद्य सब्सिडि के रूप में की जाती है । इसके आलावा, निगम को हुई मार्गस्थ और भण्डारण कमियों / हानियों की प्रतिपूर्ति भी इनको नियमित करने के बाद की जाती है । 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरन भारतीय खाद्य निगम की अनुमानित आवश्यकताओं के प्रति

सरकार द्वार भारतीय खाद्य निगम को निम्नानुसार सब्सिडि की राशि रिलीज की गई थीः—

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**वह राशि जिसके लिए संशोधित अनुसार के स्तर पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुरोध किया गया / अनुमान लगाया गया**	**सरकार द्वारा रिलीज की गई राशि**
1994-95	4915	4509
1995-96	6054	4960
1996-97	6878	5166
1997-98	9013	7500*

*इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 28 करोड़ रूपये शामिल है ।

(घ) विभिन्न स्थानों पर खाद्यानों के संचलन, भण्डारण और हैंडलिंग़ के फलस्वरूप हानियां होती है । 1994-95 से 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यानों की हुई मार्गस्थ और भण्डारण कमियों / हानियों की राशि और सरकार द्वार इनकी की गई प्रतिपूर्व निम्नानुसार हैः—

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**केन्द्रीय परिचालन के खाते में जाने वाले खाद्यानों की मार्गस्थ और भण्डारण कमियों / हानियों की राशि जिसका दावा इसके नियमित होने के पश्चात किया जा सकता है ।**	**सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि** (*)
1994-95	200.9245	114.0532
1995-96	313.6031	185.1685
1996-97	362.6522	69.2957
1997-98	185.0000	202.2768

(स. अ.)

स. अ. संशोधित अनुमान

(*) ये अधिकांशतः पिछले वर्षो से संबंधित है और इसे रिलीज की गई कुल सब्सिडी में शामिल किया गया है जिसे भाग (क) से (ग) के उत्तर में दिखाया गया है ।

Rice Scam in Narwana

1856. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appear ing in the Rashtriya Sahara dated the 6th May, 1998, under the caption "Narwana main poune do core ka chawal ghotala";

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of F.C.I, officials who are involved in this scam and what action Government have taken against each?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) A total quantity of 21,853 bags of rice received at B.G. NARWANA from 25.4.98 to 30.4.98 was rejected as the